



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 26329 वर्ष 2026

अरुण कुमार

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : चंद्र भूषण प्रसाद, राजन मिश्रा

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

- राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने बताया कि निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और यदि जमानत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक कृषि विभाग में तकनीकी सहायक समूह-सी के पद पर कार्यरत था और आरोप है कि प्रारंभ में उससे 50,000 रुपये की मांग की गई थी। हालांकि, बातचीत के बाद इसे घटाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। इसके बाद एक जाल बिछाकर आवेदक को 20,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अधिकतम सजा सात वर्ष है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 21.4.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
- राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन मामले के तथ्यात्मक आधार पर विवाद नहीं किया।
- राज्य के विद्वान एजीए ने ऐसा कोई तथ्य या परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की है जिससे आवेदक के आपराधिक इतिहास या पूर्ववृत्त का संकेत मिले जिससे आवेदक जमानत के लिए अयोग्य हो जाए।
- राज्य का यह मामला नहीं है कि आवेदक ने निचली अदालत के समक्ष जांच या कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है।
- यह सिद्धांत कि जमानत एक नियम है और कारावास एक अपवाद है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में सर्वमान्य है। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 (10) एससीसी 51 मामले में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दोहराया है। राज्य के अधिवक्ता, माननीय अटॉर्नी जनरल ने ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बताई है जिसके आधार पर आवेदक को जमानत देने से इनकार किया जा सके।

8. राज्य के विद्वान एजीए द्वारा ऐसा कोई भी सबूत, तथ्य या परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या आरोपी का चरित्र ऐसा है कि उसकी मात्र फरार मौजूदगी गवाहों को डरा सकती है या आरोपी अपनी आजादी का इस्तेमाल न्याय को बाधित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

9. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य के विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी या परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं की गई हैं जिनसे यह संकेत मिलता हो कि आवेदक न्याय से भाग रहा है, न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है, या बार-बार अपराध करने, गवाहों को डराने-धमकाने आदि के रूप में अन्य प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न कर रहा है।

10. राज्य के विद्वान एजीए ने ऐसा कोई सबूत या परिस्थिति नहीं दिखाई है जिससे यह साबित हो कि आरोपी/आवेदक जनहित या राज्य के व्यापक हित में जमानत का हकदार नहीं है।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

12. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत मामला संख्या 01/2026 में आरोपित आवेदक- **अरुण कुमार**, जिसे पुलिस स्टेशन जनकपुरी, जिला सहारनपुर से पुलिस स्टेशन ए.सी.ओ. सहारनपुर, जिला सहारनपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा नहीं।

iii. आवेदक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो और/या आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।

iv. आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

v. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

vii. यदि आवेदक अपना आवासीय पता बदलता है, तो आवेदक संबंधित न्यायालय को नए आवासीय पते की लिखित सूचना देगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

4 अगस्त, 2026

वीएमए

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।